Gujarat Government's proposal for setting up Power Project in Madhya Pradesh in Joint Venture

217. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat have submitted a proposal to set up 1300 M.W power project in Madhya Pradesh in joint ventrue with Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan Government;

(b) what is the estimated cost of project;

(c) what is the proposed allocation of electricity to each state;

(d) whether any private or public enterprises will invest in this project; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (e) The Government of Gujaat have not submitted a proposal to set up a 1300 MW power project in Madhya Pradesh as a joint venture with Haryana, Madhya Pradesh and Rajasthan.

Transmission and distribution losses in UPSEB

218. SHRI RAM RATAN RAM: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what are the transmission losses of the Electricity Board of Utter Pradesh for the current year; and

(b) what steps are being taken by the CEA for reducing the transmission losses;

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) The transmission and distribution losses of UPSEB for the year 1991-92 were 25.26%. The target for the year 1992-93 is to bring down the losses to 24%.

(b) Action for reduction of T & D losses is taken by the State Electricity Boards (SEBs). The Central Electricity Authority (CEA) has, however, issued guidelines to the State Electricity Boards and Electricity Departments (EDs) for reduction of T & D losses and have also started monitoring the physical progress of Action Plans prepared by the SEBs/EDs for the systematic reduction of the T & D losses.

The guidelines issued by CEA include directions to conduct energy audit, segregation of T & D losses into losses in primary transmission system and secondary transmission & distribution system, preparation of system improvement schemes to bring about reduction in T & D losses which, *inter-alia* include measures like installation of good quality and tamper proof energy meters and their maintenance and installation of capacitors to improve the voltage profile.

An incentive scheme has also been introduced by the Government of India with effect from 1987 for bringing about reduction in T & D losses.

देश में उत्पादित पन-बिजली और तापीय बिजली का अनुपात

219. **श्री राम जेठमलानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली का अधिकांश उत्पादन पन-बिजली और तापीय बिजली क्षेत्र में होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1962-63 में इन दोनों बिजली उत्पादन क्षेत्रों के मध्य औसत अनुपात 51:49 था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि धीरे-धीरे यह संतुलन बिगड़ता गया और अब इन दोनों बिजली उत्पादन क्षेत्रों के मध्य औसत अनुपात लगभग 30:70 रह गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में पन-बिजली क्षेत्र में बिजली उत्पादन की क्षमता अनुमानतः 600 बिलियन मेगावट है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और बिजली उत्पादन के इन दोनों क्षेत्रों में औसत अनुपात इतना अधिक असंतुलित हो जाने के कारण क्या हैं; और

(च) क्या यह भी सच है कि पन-बिजली क्षेत्र में

बिजली उतपादन की लागत तापीय बिजली क्षेत्र की तुलना में कम है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) देश में विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत जल विद्युत, ताप विद्युत और न्यूक्लीय है। तथापि न्यूक्लीय स्रोत का विद्युत उत्पादन अन्य दोनों स्रोतों के विद्युत उत्पादन की अपेक्षा कम है।

(ख) और(ग) वर्ष 1962-63 में समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत एवं ताप विद्युत का औसत अनुपात लगभग 50.6:49.4 था। अब 1.11.1992 की स्थिति के अनुसार देश में समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत का योगदान 27.54 है। जल विद्युत उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना पर अधिक बल दिया जाना है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1987 में किए गए जल विद्युत पुर्नमूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार 60% भार अनुपात पर देश में जल विद्युत शक्यता 84040 मेगावट होने का अनुमान लगाया गया है इसकी अपेक्षा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 600 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) जल विद्युत ताप विद्युत का प्रतिकूल मिश्रण होने का कारण, जल विद्युत परियोजनाओं की दीर्घ निर्माणाधीन अवधि होना, पर्यावरणीय समस्या, आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक परिस्थितियां, अन्तर्राज्यीय जल संबंधी विवाद तथा अधिकांश जल विद्युत शक्यता का दूर दराज के क्षेत्रों में भार केन्द्रों से दूर अवस्थित होना है।

(च) जल विद्युत उत्पादन की लागत, विद्युत उत्पादन के अन्य स्रोतो की अपेक्षा कम होती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की लागत

220. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1992 के दी "ओब्जवर" में "पावर जेनरेशन कास्ट 38 परसेंट चीपर इन प्राइवेट सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले विद्युत उत्पादन लागत का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने का विचार रखती है; और

(घ) क्या ऐसी जानकारी गैर-सरकारी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विद्युत उत्पादन की लागत भिन्न-भिन्न परियोजना पर भिन्न-भिन्न होती है तथा यह परियोजना के स्थान, प्रकार, क्षमता तथा अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है।

बिहार में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये योजना

221. **श्री गया सिंह:**
श्री सुनील बसुराय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा सरकार बिहार में बिजली की कमी और आवश्यकता को पूरा करने का विचार रखती है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव संयंत्र में 1 अक्तूबर, 1992 की रात को कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कुछ अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस भीषण दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) 8वीं योजना के दौरान, बिहार में राज्य क्षेत्र में 476.9 मे०वा० तथा निजी क्षेत्र में 500 मे०वा० क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य को पूर्वी क्षेत्र में स्थापित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से भी इसका देय हिस्सा प्राप्त होगा। बिहार में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु किये जा रहे अन्य विभिन्न उपायों में ये शमिल है—

विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना, पड़ोसी प्रणालियों एवं राज्यों से सहायता प्रदान करना।

(ख) कहलगांव सुपर ताप परियोजना के यूनिट-1